(ग) इस तरह से कितने वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और सरकार द्वारा उन्हें आदिवासियों को सौंपने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) संगत सूचना एकत्र की जा रही है।

लुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियां

2437. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक जनजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि वे तेजी से बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई और पक्षपातपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था को सहन नहीं कर पाई;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जनजातियां कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या सरकार इन जनजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए कोई पहल कर रही है/करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनजातियों के संरक्षण और विकास करने के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिल क-आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किये जाते हैं। भारत सरकार आदिम जनजाति समूहों के लिए विशेष आबंटन करती है तथा यहां तक कि सम्पूर्ण के सिद्धान्त पर भी बल नहीं देती है। आदिम समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर शुरू किए जाते हैं। आदिम जनजाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान आदिम जनजाति समूहों के विकास संबंधी एक नई योजना कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक जनजाति तथा इसके पर्यावरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना में अन्तःनिर्मित लचीलापन होगा।

Mining of Commercial Basis in Himachal Pradesh

2438. **SHRI ANIL SHARMA**: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of areas identified in Himachal Pradesh where mining can take place on a commerical basis;

(b) the steps taken to develop these areas so as to tap the national resources of Himachal Pradesh;

(c) the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Mining on a commercial scale is going on in Bilaspur district for limestone, in Mandi district for salt (rock), in Sirmur district for barytes and limestone and in Solan district for limestone and shale. Besides, five areas have been identified in Himachal Pradesh.

(b) and (c) The development of areas for exploitation of mineral resources is primarily the responsibility of the State Government. However, Geological Survey of India under the Ministry has carried out survey to identify mineral deposits.

The details of the five areas identified are as under:—

(i) Limestone: 292.010 hect., in Shind and Baroh Areas of Chamba district.

(ii) Limestone: 725.857 hect., in Surendranagar Mandi district and

(iii) Limestone: 450 hect., in village Alsindi in Mandi district.

(iv) Limestone: About 238 hect., near village Sujala in Solan district.

(v) Rock-salt: About 41.88 hect. in Darang area, Mandi district.

(d) Question does not arise.

SAIL Stock Yard at Dharmanagar

2439. **SHRI KHAGEN DAS**: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for SAIL stock yard at Dharmanagar; and

(b) by when the stock yard will become functional?